



अब 100% इथेनॉल से दौड़ेंगी गाड़ियां, सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सोमवार को केंद्रीय मोटर व्हीकल नियमों में किए गए बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए 100 प्रतिशत इथेनॉल (ई100) और ई85 ईंधन से चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को आधिकारिक रूप से अनुमति दे दी है। अब ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को अनुमति मिल गई है, जो 100 प्रतिशत



तक एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चल सकते हैं। यह बदलाव ऐसे समय में आया है, जब कुछ कार निर्माता कंपनियां जल्द ही अपने ई100 मॉडल्स मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इन संशोधनों के जरिए उत्सर्जन से जुड़े नियमों को अपडेट किया गया है, जिसमें ई85 के साथ-साथ ई100 को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, ई85 और ई100 का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जा सकता है, जिन्हें विशेष रूप से इनके उपयोग के लिए डिज़ाइन और प्रमाणित किया गया है। हालांकि, अन्य वाहनों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। जो वाहन ई20 या सामान्य ईंधन का उपयोग करते हैं, वे ई85 या ई100 ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस अधिसूचना के तहत, मौजूदा वाहनों के मालिकों को न तो ई85 ईंधन पर स्विच करने की जरूरत है और न ही उन्हें अभी या भविष्य में अपने वाहनों में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है। ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इन विशेष वाहनों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे एक ही प्यूल टैंक में पेट्रोल और एथनॉल के विभिन्न अनुपातों पर

आसानी से चल सकें। वाहन के सर्टिफिकेशन के आधार पर यह मिश्रण ई85 या 100 प्रतिशत एथनॉल (ई100) तक हो सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि सामान्य पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल का फॉसिल कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। एथनॉल के अधिक मिश्रण का उपयोग करने से वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन

को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, एथनॉल का अधिक उपयोग कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता को भी कम करेगा। इस फैसले के बाद आम कार चालकों और मौजूदा वाहन मालिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है:

मौजूदा वाहनों पर लागू नहीं: सामान्य पेट्रोल या ई20 ईंधन पर चलने वाली वर्तमान गाड़ियां ई85 या ई100 ईंधन का उपयोग नहीं कर सकती हैं।

कोई अनिवार्य बदलाव नहीं: सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अधिसूचना के तहत मौजूदा वाहन मालिकों को न तो ई85 पर स्विच करने की जरूरत है और न ही उन्हें वर्तमान या भविष्य में अपने वाहनों में किसी भी तरह का संशोधन कराने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरा किया रक्षाबंधन का वादा, आशा सहयोगिनी बहनों को मिला उपहार

आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि

अब प्रतिमाह मिलेंगे 5 हजार 455 रुपये,

1 अक्टूबर 2026 से देय होगा लाभ

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की आशा सहयोगिनी बहनों से रक्षाबंधन के अवसर पर किए गए वादे को पूरा करते हुए उन्हें मानदेय में वृद्धि की सौगात दी है। इससे प्रदेश में आशा सहयोगिनियों को अब 5 हजार 455 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार आशा सहयोगिनियों का मानदेय 4 हजार 959 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार 455 रुपये प्रतिमाह किया गया है तथा इसका भुगतान 1 अक्टूबर 2026 से देय होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने राखी के अवसर पर आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि का वादा किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार के इस निर्णय से आशा सहयोगिनियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन मिलेगा।

राजस्थान को केंद्र से मिले 16,619 करोड़

छह महीने में योजनागत बजट पर 1.01 लाख करोड़ खर्च, पिछले साल से 16.28% ज्यादा खर्च

जयपुर (कासं)। राजस्थान को केंद्र सरकार से सितंबर 2026 तक 16 हजार 619.72 करोड़ का फंड मिला है। यह फंड अलग अलग योजनाओं के लिए है। केंद्र से मिलने वाला फंड 2025-26 की तुलना में 8.18% ज्यादा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने केंद्र से मिलने वाले फंड और केंद्र व राज्य की योजनाओं पर सितंबर तक हुए खर्च के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्यौरा दिया है। सीएस वी श्रीनिवास ने एक्स पर लिखा- सितंबर 2026-27 के आखिर तक राजस्थान में योजनागत बजट खर्च 1 लाख 01 हजार 969.52 करोड़ रुपए रहा। यह 2025-26 की इसी अवधि के 87,695.12 करोड़ रुपए के खर्च की तुलना में 16.28% की बढ़ोतरी है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्य सचिव ने एक्स पोस्ट के जरिए केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी ब्यौरा साझा किया है। मुख्य सचिव के मुताबिक सितंबर 2026-27 के आखिर तक केंद्र से सहायता वाली योजनाओं के तहत 12,773.84 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साल 2025-26 में इसी अवधि के दौरान यह खर्च 10,650.56 करोड़ रुपए था। पिछले साल की इस अवधि के खर्च की तुलना में 19.94% ज्यादा है। केंद्र सरकार से सितंबर लास्ट तक कुल 16,619.72 करोड़ रुपए राज्य को मिले जो 2025-26 की तुलना में 8.18% ज्यादा है। प्रदेश में अप्रैल से सितंबर के छह महीने की अवधि में राजनिवेश पोर्टल पर 11,739.27 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्य सचिव के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच 31,892 आवेदनों को मंजूरी दी गई। यह पिछले पूरे वित्त वर्ष में दी गई 29,536 मंजूरियों से ज्यादा है।

रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला, आधुनिक हथियारों से लैस होगी सेना

भारतीय सेना होगी और ताकतवर, 2.12 लाख करोड़ की खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों को ताकत बढ़ाने के लिए करीब 2.12 लाख करोड़ रुपये की खरीद योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत सेना के लिए आधुनिक वाहन, तोप प्रणाली, हेलिकॉप्टर, हवाई रक्षा प्रणाली और निगरानी करने वाले ड्रोन सहित कई तरह के उपकरण खरीदने का रास्ता साफ हुआ है। इनसे सेना की दुर्गम इलाकों में पहुंच, निगरानी, दुश्मन के हवाई खतरों से सुरक्षा और युद्ध के दौरान कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने विभिन्न रक्षा बलों की पूंजीगत खरीद से जुड़े प्रस्तावों को करीब 2,12,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी है। इस मंजूरी को स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) कहा जाता है। इसका अर्थ है कि संबंधित खरीद प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक प्रशासनिक सहमति मिल गई है। यह पूरी खरीद प्रक्रिया के अंतिम रूप से पूरा होने या सभी उपकरणों की तत्काल आपूर्ति की मंजूरी के समान नहीं है। इस फैसले का उद्देश्य सशस्त्र बलों को आधुनिक



जरूरतों के अनुरूप बेहतर उपकरण उपलब्ध कराना है।

भारतीय सेना के लिए कई तरह के आधुनिक उपकरण खरीदने को मंजूरी दी गई है। इनमें हार्ड मोबिलिटी व्हीकल यानी अधिक आवाजाही क्षमता वाले वाहन, स्वचालित ट्रैक वाली तोप प्रणाली, गन शॉट रिसप्लस सिस्टम, हल्के बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर, बेहद कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और प्लेटफॉर्म आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली शामिल हैं। इसके अलावा लंबी दूरी तक काम करने वाले मानव रहित विमान, निगरानी करने वाले यूएवी, एकीकृत



‘साहब, मैं सरपंच हूं, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, ‘मैं भी तो एक दिन सरपंच ही था’

जयपुर (कासं)। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की राजनीतिक सरगमियों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान जब एक स्थानीय प्रतिनिधि ने उनसे कहा, ‘साहब, मैं सरपंच हूं, तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए सहज भाव से जवाब दिया, ‘मैं भी तो एक दिन सरपंच ही था’। मुख्यमंत्री की यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी कार्यकर्ता उठाके लगाकर हंस पड़े। सीएम भजनलाल शर्मा का यह बयान केवल एक मजाक या सहज संवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा सियासी संदेश भी छिपा हुआ है। खमेरा स्थित भाटिया महादेव मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने इस बयान के जरिए

पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। उन्होंने मंच पर बैठे जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी की तर्फ इशारा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत के दम पर बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए सहज भाव से दूध निकाला है, खेत में हल चलाया है और सरसों की कटाई की है।’ खुद को किसान और पूर्व सरपंच बताकर उन्होंने साफ संदेश दिया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की तकलीफों को सबसे बेहतर समझती है।

महिलाओं की भागीदारी और युवाओं पर की बात- अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम सियासी

साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने में मदद करेगी। इससे सेना को अपनी टुकड़ियों की गति के अनुरूप तोपों की राकड़ क्षमता इस्तेमाल करने में सहूलियत मिलेगी। गन शॉट रिसप्लस सिस्टम सैनिकों को गोलीबारी से जुड़ी जानकारी और आसपास की स्थिति का वास्तविक समय में आकलन करने में मदद करेगा। इससे सेना को खतरों की पहचान और जवाबी कार्रवाई के लिए बेहतर जानकारी मिल सकेगी।

हल्के बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, दोनों के इस्तेमाल के लिए प्रस्तावित हैं। इनका उपयोग टोह लेने, निगरानी करने, लड़ाकू अभियानों, सैनिकों को खोजने और बचाने तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जैसे कार्यों में किया जाएगा। वहीं, बेहद कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली नए प्रकार के छोटे हवाई खतरों से निपटने के लिए तैयार की गई है। आधुनिक युद्ध में छोटे ड्रोन और दूसरे हवाई उपकरण सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते हैं। ऐसे में यह प्रणाली सेना की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। प्लेटफॉर्म आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली का उद्देश्य आधुनिक युद्धक्षेत्र में टैंकों की सुरक्षा और उनके जीवित बचने की संभावना बढ़ाना है।

जीत की हैट्रिक से सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगा भारत

वेलिंगटन (एजेंसी)। विपरीत परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन कर पांच मैचों की सीरीज में दो मुकाबले जीत चुकी भारतीय टीम मंगलवार को हेनरी स्टेडियम में होने वाले तीसरे टी-20 में जीत दर्ज कर श्रृंखला विजय करने के इरादे से उतरेगी। वहीं मेजबान न्यूजीलैंड पर सीरीज में वापसी करने का दबाव रहेगा। भारत की पहली जीत 226 रनों के सफल पीछा से मिली, जो पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में भारत का सबसे बड़ा सफल चेज है। संजु सैमसन के 67 रनों ने पारी की गति दी, जबकि श्रेयस अय्यर और नमन धीर के योगदान ने यह सुनिश्चित किया कि जरूरी रन-रेट इतना न बढ़ जाए कि उसे हासिल करना नामुमकिन हो जाए। यह भारत की बल्लेबाजी की गहराई का शानदार प्रदर्शन था, साथ ही यह याद दिलाने वाला भी कि एक सफल चेज के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि कई खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है।

दूसरा मुकाबला एक अलग तरह की परीक्षा लेकर आया। 181 रनों का पीछा करते हुए भारत के पांच विकेट सिर्फ 70 रन पर गिर गए थे, और ऐसा लगने लगा कि भारत की बढ़त हाथ से फिसल रही है। न्यूजीलैंड ने सेंटनर की स्पिन के जरिए दबाव बना दिया था, और भारतीय टॉप ऑर्डर कोई मजबूत नांव नहीं रख सका था। फिर तिलक वर्मा ने 26 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए, जिसमें उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी का अच्छा साथ मिला, और इस साझेदारी ने मैच का रुख ही बदल दिया। सातवें विकेट के लिए उनकी 69 रनों की अटूट साझेदारी ने दिखा दिया कि भारत के पास मुश्किल हालात से उबरने का जज्बा है। नमन धीर के तेज-तर्रार 31 रनों ने भी इस चेज को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड के लिए सबक बिल्कुल सही था: विकेट लेना तो बस आधा काम है। विरोधी टीम को फिर से संभलने से रोकना भी जरूरी है। भारत के पांच विकेट गिर जाने के बावजूद उन्हें जीत हासिल करने देना, मेजबान टीम के लिए काफी निराशाजनक रहा होगा। मेजबान टीम को खिलाड़ियों की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी बाकी बचे टी-20 मैचों से बाहर हो गए हैं, जबकि लॉकी फर्ग्युसन वेलिंगटन वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। उनकी गैर-मौजूदगी से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी विभाग में अनुभव और भरोसेमंद विकल्पों की कमी हो गई है।

भारत आदिवासी पार्टी पर साधा निशाना

विपक्षी राजनीति पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिना नाम लिए ‘भारत आदिवासी पार्टी’ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक पार्टी इलाके के भोले-भाले युवाओं को भड़काकर गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। सीएम ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे युवाओं को सही दिशा दिखाएं और भरोसा दिलाया कि सरकार हर हाथ को काम और रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत चुनावों के बीच मुख्यमंत्री का यह बयान कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और गांव-गांव तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने में मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

और प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली सप्लाई देने की बात दोहराई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ बढ़ रही है। आगामी दिनों में महिलाओं को सीएम ने कहा कि आने वाले समय में इस इलाके में भारी उद्योग और पर्यटन के जरिए 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने

लोकजीवन

औद्योगिक विकास की कीमत चुका रही ज़िंदगी

वर्तमान में ऊर्जा, सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण आदि से संबंधित सामान और उपकरण बड़े पैमाने पर उद्योगों में ही बनाना संभव है। इसलिए दुनिया भर में उद्योगों की स्थापना की होड़ लगी रहती है। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं औद्योगीकरण पर ही टिकी हुई हैं, इसलिए एक ही उद्योगों से पैदा होने वाली पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय समस्याओं पर बोलना नहीं चाहता। लेकिन हर सहनशीलता की भी एक सीमा है। उद्योग एक ओर रोजगार देकर आम आदमी को राहत देते हैं, तो दूसरी ओर हवा, पानी, मिट्टी को प्रदूषित करके जीवनयापन की स्थितियों को बीमारियों के भंवर में फंसा देते हैं। पर्यावरण को पहुँचने वाले नुकसान के आधार पर उद्योगों को शुन्य से एक सौ के स्केल से मापा जाता है। 60 सूचकांक से ज्यादा प्रदूषक उद्योगों को लाल सूची में डाला गया है। सीमेंट, खनिज तेल रिफाइनरी, बड़े स्तर का खनन, ताप विद्युत परियोजनाएँ और रासायनिक उत्पादन इकाइयों को इस श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के लिए पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत उद्योग स्थापना और चालू करने के लिए स्वीकृति के सख्त प्रावधान हैं। दूसरी श्रेणी संतरी है। इसमें 41 से 59 प्रदूषण सूचकांक तक के उद्योग आते हैं। इसमें कम प्रदूषक गतिविधि वाले उद्योग आते हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्टोन क्रशर, ईट भूँडे और मध्यम दर्जे के उत्पाद। जैसे लिए सामान्य स्थापना और प्रचालन स्वीकृतियां लेनी होती हैं। 21 से 40 तक प्रदूषण सूचकांक वाले उद्योग आते हैं। इसमें आरा यम्रीनें, पारंपरिक शिल्प और छोटे मसाला पिसाई इकाइयां आती हैं। इनके लिए स्वीकृतियां तो चाहिए होती हैं, किन्तु लंबे समय तक स्वीकृति प्रदान की जाती है। चौथी श्रेणी खेते श्रेणी है। 0 से 20 प्रदूषण सूचकांक वाले उद्योग इसमें आते हैं। इसमें सौर ऊर्जा प्लांट, वायु ऊर्जा प्लांट और बाईसिकल असेंबली जैसे उद्योग आते हैं। इनके लिए स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना मात्र देनी होती है। हिमाचल में बड़ी, बरोटीवाला, नालागढ़ में सबसे ज्यादा उद्योग स्थापित हैं। करीब 3000 इकाइयां यहां स्थापित हैं जिनमें से 380 लाल श्रेणी की, 1400 संतरी श्रेणी की हैं। इसमें से 500 के लगभग इकाइयां जहरीली गैसें वातावरण में छोड़ रही हैं। कुछ के पास तो प्रचालन स्वीकृतियां भी नहीं हैं। अधिकांश अपशिष्ट उपचार संयंत्र का क्षमता के हैं या अकुशल हैं। शिवालिक अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट भी मनमर्जी से काम करता है। कई उद्योगों पर प्रदूषित पदार्थों को जमीन में पंप करके डाल देने का आरोप है। यह राज्य के अंदर और पड़ोसी राज्यों में भी स्वास्थ्य से बड़े खिलवाड़ का मामला है। अतः पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह औद्योगीकरण के अंध विरोध का भी मामला नहीं है। किन्तु टिकाऊ और जन अभिमुख विकास के लिए औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण होना ही चाहिए, वरना विकास का अर्थ ही अनर्थ में बदल जाता है। यहां से प्रदूषित वायु और जल पंजाब की भी प्रभावित कर रहा है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच के बाद हिमाचल के बोर्ड को लिखा भी है कि इस क्षेत्र का प्रदूषित अपशिष्ट सतलुज तक पहुंच रहा है। अवैध डंपिंग से रिस कर कुछ अपशिष्ट सिरसा नदी को प्रदूषित कर रहा है जिसका असर हरियाणा तक हो रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट को इस तरह स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने नहीं दिया जा सकता।

विशेषकर कैंसर जैसे रोगों का फैलाव राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो गया है। बीबीएन में काम करने वाले मजदूर या अन्य कार्यकर्ता भी इस दंश से बचे नहीं हैं। अशुद्ध जल के कारण पीलिया जैसे रोग आम हैं जिसकी चपेट में आकर कई जान गंवा चुके हैं। औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिए इलाज की भी उचित व्यवस्थाएं नहीं हैं जिसके चलते मुश्किल से न्यूनतम मजदूरी पर काम करने वाले महंगे इलाज तक पहुंच ही नहीं पाते। बीबीएन विकास योजना में ही उद्योग, बौत्स्नर, गैसों का उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाना और रासायनिक कणों के उत्सर्जन को वायु प्रदूषण का कारण माना गया है, जिससे खांसी, गले में खराश, बलाग, न्वास, ब्रोंकाइटिस, अन्य रक्शन संबंधी रोग, फेफड़ों के कार्य में कमी, आंखों में जलन जैसे रोगों में वृद्धि हुई है। 2026 के एक वैज्ञानिक अध्ययन में 50 भूजल के नमूनों का अध्ययन किया गया था, जिसमें 78 फीसदी नमूनों में जल पीने योग्य नहीं पाया गया। संधिया और फ्लोराइड की उपस्थिति चिंताजनक मानी गई, जिससे चरम रोग, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर का खतरा बढ़ा है।

फ्लोराइड से दांतों का प्लूरोंसिस आदि का खतरा बढ़ा है। बच्चों के लिए यह खतरा ज्यादा है। प्रदूषण केवल औद्योगिक स्थल तक ही सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि प्रदूषित हवा और पानी आसपास और नदी के माध्यम से नीचे दूर तक पहुंच जाता है। इसलिए एकलुज तक यह खतरा फैलता जा रहा है। इसी कारण गत दिनों प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन में पंजाब से भी लोग शामिल हुए। अतः अब हिमाचल के औद्योगिक सफ़र को निरापे्र और टिकाऊ औद्योगिक विकास के अनुकूल बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण पर सख्त कदम उठाने का समय आ गया है, जिसके लिए एकलुज पर उपचार संयंत्रों का ठीक से काम करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और केंदुवाल स्थित सामूहिक अपशिष्ट संशोधन संयंत्र की क्षमता-वर्धन और सतत कार्यशीलता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस कार्य में स्थानीय स्तर पर कार्यरत सामाजिक संगठनों का सहयोग लेना होगा।

ब्रिक्स संसदीय मंच वैश्विक चुनौतियों के समाधान का सशक्त माध्यम : देवनानी

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित संसद में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। देवनानी ने कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान, विभिन्न देशों में संसदीय समन्वय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, संसद एवं विधानसभाओं में सार्थक बहस और पक्ष-विपक्ष की जिम्मेदारी सहित विभिन्न विषयों पर ब्रिक्स सम्मेलन महत्वपूर्ण है। देवनानी ने कहा कि ब्रिक्स देशों की संसदीय बैठक का विशेष महत्व है, क्योंकि इन देशों में विश्व की आधी आबादी निवास करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, आतंकवाद और सह-अस्तित्व जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इन विषयों पर विभिन्न देशों की संसदों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है, ताकि सभी देश मिलकर समस्याओं का समाधान निकाल सकें।

मानव जीवन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता-

देवनानी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थि में, जब विभिन्न देशों के बीच तनाव और क्षेत्रवाद जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, तब मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र की जननी एवं आत्मा है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह

वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए देशों के साथ मिलकर प्रयास करे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण-

देवनानी ने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया प्रभावशाली हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विश्व के विभिन्न संगठनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में भारत का अधिकार बनता है। उन्होंने कहा कि कई देश भारत को इस दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है। जब तक संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन भारत जैसे देशों को समुचित रूप से सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक उनकी क्रियान्वयन की प्रभावशीलता में अपेक्षित सुधार नहीं आ सकेगा। देवनानी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम में शामिल विभिन्न देशों में से कई देश भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और विदेश नीति के सफल प्रयासों के कारण आज विश्व के अधिकांश बड़े और छोटे देश भारत के समर्थन में खड़े हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं में सार्थक बहस और जनसमस्याओं पर चर्चा आवश्यक-

स्पीकर देवनानी ने नगरपालिका, पंचायतों, विधानसभाओं और लोकसभा तक

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार तथा नवाचार की संभावनाएं बताईं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां प्रत्येक पांच वर्ष में नगरपालिका, पंचायतों, विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव होते हैं। पिछले वर्षों में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। पंचायतों में 80 प्रतिशत से अधिक लोगों की सहभागिता देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी बढ़ने के साथ ही लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। स्थानीय समस्याओं के समाधान से लेकर राज्य और केंद्र तक आमजन की आवाज पहुंच रही है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता बढ़ रही है।

देवनानी ने कहा कि संसदीय मंचों की स्थापना सार्थक बहस और जनसमस्याओं पर चर्चा के लिए है, लेकिन वर्तमान में इन मंचों पर सार्थक बहस नहीं हो पा रही है और अधिक समय अवरोधों में व्यतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष, दोनों का दायित्व है कि वे मिलकर जनता की समस्याओं को सदन में उठाएं और उनके समाधान की दिशा में कार्य करें।

संसद एवं विधानसभाओं में सार्थक बहस की परंपरा को मजबूत करना आवश्यक-

देवनानी ने विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारी तथा सदन की कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में कहा कि समय-समय पर मर्यादाएं और परंपराएं निर्धारित होती रही हैं। आवश्यकता उनके पालन की है। उन्होंने अपने पूर्व के संसदीय



अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मधु लिमये, दंडवते और प्रकाश शास्त्री जैसे नेताओं के समय लोकसभा में बहस का एक स्तर होता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विपक्ष अपनी अपेक्षित भूमिका का समुचित निर्वहन नहीं कर पा रहा है। देवनानी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस दिशा में सक्षम हैं और कई मामलों में सर्वदलीय बैठकें भी करते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी उन्होंने इस प्रकार की पहल की है। सभी विधानसभाओं और लोकसभा में अधिक से अधिक बैठकें आयोजित होनी चाहिए तथा महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर अधिक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन ऐसा मंच बना चाहिए, जहां केवल समय व्यतीत न हो, बल्कि असमति के बावजूद सार्थक संवाद हो और

जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं।

संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी-

स्पीकर देवनानी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने और पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप के संबंध में कहा कि दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे समन्वय के साथ कार्य करें। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था रखते हुए सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा निर्माण से बचना आवश्यक-

देवनानी ने कहा कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा निर्माण करने की एक होड़ लगी हुई है। इससे बचना आवश्यक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए पक्ष और विपक्ष, दोनों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा तथा संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान और विश्वास बनाए रखना होगा।

संसदीय लोकतंत्र की प्रभावशीलता सार्थक बहस और जन समस्याओं के समाधान में-

देवनानी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की प्रभावशीलता सार्थक बहस, जनसमस्याओं के समाधान, परस्पर समन्वय और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था से सुनिश्चित होती है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए जनहित को सर्वोच्च

किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, उर्वरकों के साथ जबरन अन्य उत्पाद बेचने वाले आदान विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई

कृषि आदान विक्रेताओं की गिरानी के लिए मोबाइल ऐप विकसित, अब तक 9 हजार से अधिक निरीक्षण, 250 से अधिक विक्रेताओं पर कार्रवाई

राज्य सरकार का सख्त संदेश—किसानों का आर्थिक शोषण करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा तथा कृषि आदानों की गुणवत्ता, उचित मूल्य एवं पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता एवं प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश में उर्वरकों की कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली, जबरन टैगिंग तथा अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक निरीक्षण एवं गिरानी अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग ने निरीक्षण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से अब तक प्रदेश में 9,000 से अधिक कृषि आदान विक्रेताओं के निरीक्षण किए जा चुके हैं तथा विभिन्न अनियमितताओं के मामलों में 250 से अधिक विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई राज्य सरकार की किसानों के हितों के प्रति संवेदनशीलता तथा कृषि आदान वितरण

व्यवस्था में अनियमितताओं के प्रति सख्त रुख को दर्शाती है।

मोबाइल ऐप से निरीक्षण व्यवस्था हुई सुदृढ़

विभाग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से कृषि आदान विक्रेताओं के निरीक्षण को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है। इससे निरीक्षण संबंधी सूचनाओं के संकलन, गिरानी एवं समीक्षा में सुविधा होगी। इस पहल का उद्देश्य निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाना तथा अनियमितताओं की समय पर पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा प्रदेशभर में कृषि आदान विक्रेताओं के निरीक्षण अभियान को निरंतर जारी रखा जाएगा।

जबरन टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, कंपनियों की भी जवाबदेही तय

कृषि आयुक्तालय द्वारा 23 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसानों को यूरिया, डीएपी अथवा अन्य अनुदानित उर्वरकों के साथ जंक, सल्फर, कीटनाशक, जैव उर्वरक या अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर केवल खुदरा विक्रेताओं ही नहीं, बल्कि संबंधित थोक विक्रेताओं तथा उर्वरक निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता कंपनियों की भूमिका को भी जांच की जाएगी।

दोषियों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण एवं एफआईआर तक की कार्रवाई

कृषि विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अनियमितताओं की पुष्टि होने पर संबंधित विक्रेताओं एवं कंपनियों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के लागू प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए। प्रकरण की गंभीरता एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार विक्रय प्राधिकार-पत्र का निलंबन अथवा निरस्तीकरण तथा आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकेगी।

विशेष निरीक्षण दल करेंगे औचक जांच

प्रदेश के सभी जिलों में विशेष निरीक्षण दल गठित कर उर्वरक कंपनियों, गोदामों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का

नियमित एवं औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता, स्टॉक, बिक्री अभिलेखों, बिलों तथा अन्य कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

शिकायतों पर 24 घंटे में प्रारंभिक कार्रवाई

किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक जिले में उर्वरक शिकायत प्रकोष्ठ अथवा हेल्पलाइन स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। जबरन टैगिंग एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई शुरू करने तथा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी तय होगी जिम्मेदारी

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण, शिकायतों के निस्तारण एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्देशों की अनुपालना में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विद्युत वितरण निगमों की 10वीं राष्ट्रीय कांफ्रेंस का जयपुर में आयोजन पहली बार राजस्थान में डिस्ट्रिब्यूशन यूटिलिटी मीट 27 एवं 28 अक्टूबर को

जयपुर (कासं)। इण्डिया स्मार्ट ग्रिड फोरम तथा राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग की सहभागिता से 27 एवं 28 अक्टूबर को जयपुर में डिस्ट्रीब्यूशन यूटीलिटी मीट– 2026 का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर तथा मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास होटल ‘ललित’ में मंगलवार प्रातः 10 बजे इसका शुभारम्भ करेंगे। विद्युत वितरण क्षेत्र की इस 10वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राज्यों के डिस्कॉम्स, केन्द्रीय एवं राज्य विद्युत नियामक आयोगों के प्रतिनिधियों सहित देश के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की लगभग सभी प्रमुख कम्पनियों, संस्थाओं के शीर्ष अधिकारी तथा ऊर्जा विशेषज्ञ आदि भाग लेंगे।

7 सत्रों में होगी पावर डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर की मजबूती पर चर्चा

राजस्थान को पहली बार इस महत्वपूर्ण आयोजन का सुअवसर मिला है। दो दिवस के दौरान 7 विभिन्न सत्रों में विद्युत वितरण तंत्र में हो रहे नवाचारों, नीतिगत सुधारों, डिस्कॉम्स के आर्थिक सुदृढ़ीकरण, डिजिटाइजेशन, एआई द्रुतस् एवं उनके बढ़ते उपयोग, एनर्जी ट्रॉजिशन के साथ शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ने, ग्रिड आधुनिकीकरण एवं इसके स्मार्ट प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते अवसरों, ऊर्जा भण्डारण, डेटा सेंटरों एवं इलेक्ट्रिक व्हीलक चाार्जिंग के कारण बिजली की बढ़ती मांग एवं इसके समुचित प्रबंधन आदि की राह में आने वाली बाधाओं, चुनौतियों एवं उनके समाधान पर सार्थक चर्चा की जाएगी। वितरण निगम के रूप में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम इस कार्यक्रम के

आयोजक हैं। वहीं टाटा पावर, चण्डीगढ़ पावर, नोएडा पावर, बीएसईएस राजधानी पावर एवं बीएसईएस यमुना पावर आदि वितरण कम्पनियां इसकी सह-आयोजक होंगी। आयोजन की थीम ‘सहयोगी विकास के लिए विद्युत वितरण निगमों का एकीकरण’ रखी गई है। विदेशी प्रतिनिधियों का भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। यूपएसए, यूरोप, दक्षिण कोरिया और जापान आदि देशों से भी इस सेक्टर के ख्याति प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्टेक होल्डर्स भाग लेंगे। देश-विदेश के लगभग 500 से अधिक प्रतिनिधि इस आयोजन में सम्मिलित होंगे।

पहले दिन उद्घाटन एवं तीन सत्र

इस राष्ट्रीय कांफ्रेंस के प्रथम दिन मंगलवार को उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही तीन महत्वपूर्ण सत्र होंगे। प्रातः 10 बजे उद्घाटन समारोह को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के साथ ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद, कैलिफॉर्निया एनर्जी कमीशन के वाइस चेयरपर्सन सिवा गंडा, ऑल इंडिया डिस्कॉम्स सोसिएशन के महानिदेशक आलोक कुमार, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक श्रीमती शालिनी अग्रवाल, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक आरके त्यागी, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन राजेश शर्मा, नोएडा पावर के एमडी एवं सीईओ प्रेम कुमार सहित ऊर्जा क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ संबोधित करेंगे। शासन सचिव ऊर्जा सुश्री आरती डोगरा तथा इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के प्रेसीडेंट रेजी कुमार पिल्लई स्वागत वद्बोधन देंगे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पक्षधर बने विश्व समुदाय, लोकतांत्रिक संस्थाओं में सार्थक चर्चा और संसदीय मर्यादाओं का पालन आवश्यक

आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला शाश्वत संदेश है। भगवान श्रीराम का मर्यादित आचरण, माता सीता का धैर्य एवं समर्पण, लक्ष्मण का भ्रातृप्रेम और त्याग तथा भरत का सत्ता के प्रति अनासक्ति का भाव भारतीय संस्कृति के ऐसे आदर्श हैं, जो आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। देवनानी ने रावण के अहंकार के दमन का उल्लेख करते हुए इस बात को रेखांकित किया कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। वहीं, मर्यादा, सत्य, त्याग और सदाचार जैसे मूल्य मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं। रामायण का संदेश बल्कि एक देश या समाज तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी प्रासंगिक है।

देवनानी ने कहा कि दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, सद्भाव, करुणा और सामाजिक समरसता को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्रीलंका के उच्चायोग में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय मिलन समारोह ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच सांस्कृतिक संवाद, आपसी सद्भाव और भारतीय परंपराओं को साझा करने का अवसर प्रदान किया। समारोह में दीपावली के उल्लास के साथ भारतीय संस्कृति की सावभौमिक भावना और रामायण के मानवीय मूल्यों का संदेश भी प्रतिध्वनित हुआ।

सिर्फ जीम का जायका ही नहीं, त्वचा को भी खूबसूरत बनाती है चॉकलेट

चॉकलेट खाना न केवल आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, बल्कि इसे त्वचा, चेहरे या शरीर पर लगाने से रंग-रूप भी निखरता है और त्वचा मुलायम हो जाती है।



* चॉकलेट एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को दूर कर त्वचा को जवां और खूबसूरत बनाता है। त्वचा में कसाव लाता है।
* यह एंटी-इन्फ्लेमेटरी होता है, जिससे यह रूखी और संवेदनशील त्वचा के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है।
* डार्क चॉकलेट त्वचा में निखार लाने के साथ ही उसे मुलायम बनाता है और त्वचा में नमी बरकरार रखता है।
* चॉकलेट फ्लैवेनोल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता

है, जो त्वचा को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है, झुर्रियां दूर करता है और त्वचा को नमी प्रदान करता है।
* चॉकलेट में पाया जाने वाला फ्लैवेनोल रक्त चाप को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर त्वचा को कोमल बनाता है।
* चॉकलेट फेशियल आजकल खूब चलन में हैं। यह न सिर्फ

त्वचा का रंग साफ करता है, बल्कि झुर्रियां और महीन रेखाएं भी कम करता है।
* एक-तिहाई कप कोको पाउडर में 2-3 बड़ा चम्मच शहद और कुछ नींबू के रस की बूंदें मिलाएं। इस चॉकलेट फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट छोड़ दें और फिर चेहरा धुलें। इससे त्वचा मुलायम होगी, रंग साफ होगा और चेहरे पर चमक व निखार भी आएगा।
* यह चेहरे पर बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है और झुर्रियों, दाग-धब्बों को दूर करता है।

घुटने के दर्द की छुट्टी करेंगे ये 10 दमदार उपाय

अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो ये उपाय आपके काफी हद तक राहत दिला सकते हैं। आइए जानें कौन से हैं ये उपाय-

1. कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर बनाए पैड से सिंकाई करने से घुटने के दर्द में आराम मिलता है।
2. भोजन में दालचीनी, जीरा, अदरक और हल्दी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। गर्म तासीर वाले इन पदार्थों के सेवन से घुटनों की सूजन और दर्द कम होता है।
3. मेथी दाना, सोंठ और हल्दी बराबर मात्रा में मिला कर तवे या कढ़ाई में भून कर पीस लें। रोजाना एक चम्मच चूर्ण सुबह-शाम भोजन करने के बाद गर्म पानी के साथ लें।
4. रोज सुबह खाली पेट एक चम्मच मेथी के पिसे दानों में एक ग्राम कलौंजी मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें। दोपहर और रात में खाना खाने के बाद आधा-आधा चम्मच लेने से जोड़ मजबूत होंगे और किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा।
5. सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली दही के साथ खाएं।

6. हल्दी चूर्ण, गुड़, मेथी दाना पाउडर और पानी सामान मात्रा में मिलाएं। थोड़ा गर्म करके इनका लेप रात को घुटनों पर लगाएं और पट्टी बांधकर लेटें।
7. अलसी के दानों के साथ दो अखरोट की गिरी सेवन करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है।
8. बराबर मात्रा में नीम और अरंडी के तेल को

हल्का गर्म करके सुबह-शाम जोड़ों पर मालिश करें।

9. मालिश के लिए आप इन चीजों से भी तेल बना सकते हैं। 50 ग्राम लहसुन, 25 ग्राम अजवायन और 10 ग्राम लौंग 200 ग्राम सरसों के तेल में पका कर जला दें। ठंडा होने

पर कांच की बोतल में छान कर रख लें। इस तेल से घुटनों या जोड़ों की मालिश करें।

10. जोड़ों के दाने के आकार का चूना दही या दूध में घोलकर दिन में एक बार खाएं। इसे 90 दिन तक लेने से कैल्शियम की कमी दूर होगी।

8 ऐसी बातें, जो मां को बनाती है दुनिया की बेस्ट माँम

हर मां अपना बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा होता है। मां-बच्चे में भावनात्मक रिश्ता बचपन से ही जुड़ जाता है। अगर पापा की डांस से बचना हो तो मां पूरी मदद करती है। बच्चा दुखी हो तो मां उसके दुख को बांटती है। इसलिए तो वह दुनिया की सबसे बेस्ट मां होती है। आज हम आपको ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे, जो मां को बेस्ट बनाती है।

आपकी पहली टीचर



बच्चे की पहली टीचर होती है मां। क्योंकि बचपन में बच्चा जो कुछ भी सिखाता है, वह सब कुछ अपनी मां से सिखाता है, जैसे पोयम से लेकर हैंड वॉश करना है। यह सब उसे मां ही सिखाती है।

खाने को लेकर चिंता

अरे, अपना टिफिन बॉक्स पूरा क्यों नहीं खाया? आज भूख क्यों नहीं लगी तुम्हें? मां बच्चे से रोज यहीं बात पूछती है। इन्हें बातों से पता चलता है। मां को बच्चे की कितनी चिंता होती है।

पापा का गुस्सा ? मम्मी बचाओ!



मां बच्चे को बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचाती हैं। फिर वह मुसीबत कोई और हो या पापा का गुस्सा। पापा की डांस से मम्मी ही बचाती है।

ब्रेकअप के बाद...!!

अगर ब्रेकअप हो जाए तो मां दिलासा देती कहती है। अरे अरे वो तेरे लायक ही नहीं था, मैं तेरे लिए इससे अच्छी लड़की ढूँढ लाऊंगी मेरे लाल!

एक्जाम मेरा! मां की चिंता



एक्जाम अगर बच्चे का हो तो चिंता मां की लगी रहती है। रात को बच्चे के साथ बैठ कर गुजार देती है। बीच-बीच में बच्चे को गमगीन कॉफी बना कर देती है।

आपके फ्रेंड्स मां के फ्रेंड्स

अगर कभी-कभार बच्चे के फ्रेंड्स घर पर आ जाए तो मां भी उनको पूरा प्यार देती है। अपने बच्चे की तरह उनका भी खयाल रखती है। उनके साथ अपने ही बच्चे की मजाक-मस्ती करती है। बस यहीं बातों मां को बच्चे की करीब ला देती है।

आप बीमार, मम्मी परेशान



अगर बच्चा परेशान या बीमार होता है तो सबसे ज्यादा इस तकलीफ का अहसास मां को होता है। ऐसे में मां अपने सारे काम छोड़कर आपके सिरहाने बैठ जाती है। आपके सेहतमंद होने की दुआएं करती है।

आपका करियर उनका ख्वाब

आपका ख्वाब भी मां का ख्वाब बन जाता है। वह आपके करियर को लेकर काफी चिंता करती है। आपके हर वो सलहा देना चाहती है, जिनसे आपको थोड़ी-बहुत मदद मिल सके।

स्मार्टफोन पर देर रात थारी आंखों पर पड़ेगी भारी

कमी चैटिंग, कमी गेमिंग तो कमी विडियो कॉलिंग। स्मार्टफोन पर हमारी निर्भरता इस कदर बढ़ी है कि बिना इसके इस्तेमाल के न तो दिन गुजरता है और न रात में नींद आती है। हालांकि, देर रात तक लाइट बंद कर मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाना आंखों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इससे न सिर्फ ड्राई आइज की समस्या होती है बल्कि लोगों की आंखें कमजोर भी हो रही हैं। डॉक्टरों की मानें तो हर दिन ओपीडी में 20 प्रतिशत मरीज इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं। आगे की तस्वीरों में जानें, मोबाइल पर लंबा वक्त बिताने की यह आदत किस तरह सभी उम्र के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है...



मोबाइल से बढ़ रही आइज ड्राइनेस

लोकबंधु अस्पताल की डॉ. सेहलता कहती हैं एक वक्त के बाद आंखें थक जाती हैं लेकिन हम फिर भी थकी हुई आंखों से काम लेते रहते हैं। यही असली दिक्कत है। रात में मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त जब लाइट्स भी बंद कर दी जाती हैं तो स्क्रीन से निकलने वाली किरणें सीधे आंखों पर पड़ती हैं जिससे वे प्रभावी ढंग से काम करना बंद कर देती हैं। डॉ. सेहलता कहती हैं कि उनके पास हर ओपीडी में 20 से 30 ऐसे मरीज आते हैं, जो आइज ड्राइनेस का शिकार होते हैं या फिर देर रात तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की वजह से आंखों में दर्द से लेकर कम दिखने की शिकायत करते हैं। आइज ड्राइनेस के लिए ऐसी भी कुछ हद तक जिम्मेदार होता है।

मोबाइल की वजह से आंखों में प्रॉब्लम आम वजह

यंगस्टर्स अक्सर देर रात तक फॉन्टल पोर्जीशन (लेटना या गलत ढंग से बैठना) में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। अंधेरे कमरे में स्मार्टफोन की स्क्रीन पर टक्कटकी लगाए रखने की वजह से अक्सर उन्हें आंखों में इर्रिटेशन, ड्राईआइज और आंखें लाल होने की समस्या होती है। ओपीडी में आने वाले इस तरह के पेशेंट्स में ज्यादातर 20 से 40 साल की उम्र के होते हैं। मोबाइल का प्रभाव बढ़ते बच्चों पर ज्यादा होता है, जिससे आईसाइट कमजोर होती है। ऐसे पेशेंट्स को खासतौर पर फोन का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाती है।

मोबाइल चैटिंग की बात छिपाते हैं पेशेंट्स

डॉ. उमेश कुमार सोनकर कहते हैं कि बच्चे ही नहीं बड़े भी मोबाइल पर घंटों वक्त बिताते हैं। अक्सर रात में लाइट्स बंदकर चैटिंग या विडियो देखने की आदत आंखों पर बुरा असर डालती है। जब लोग हमारे पास कम दिखने जैसी शिकायत लेकर आते हैं तो हम उनका शैड्यूल पूछते हैं। ऐसे में अक्सर लोग मोबाइल पर लंबा वक्त बिताने की बात छिपाते हैं। वे यह नहीं बताना चाहते कि वे देर रात तक मोबाइल पर चैट करते हैं। इसकी बजाय वे दूसरे कारण गिनाने लगते हैं।

चश्मे की बजाए आईड्रॉप का इस्तेमाल

डॉक्टर सोनकर कहते हैं कि इस तरह के मरीजों को वह चश्मा लगाने की सलाह देने के बजाय आईड्रॉप की मदद से ठीक करने पर जोर देते हैं। इस तरह के केस में पेशेंट्स 15 दिन से लेकर एक महीने में नॉर्मल आईसाइट के लेवल पर आ जाते हैं। हालांकि, इस तरह के पेशेंट्स को डॉक्टरों से चेतावनी देते हैं कि अगर वक्त रहते वे अपनी आदत (लाइट बंद कर मोबाइल पर चैटिंग) पर काबू नहीं पाते हैं तो उनके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है।



खाने के तुरंत बाद चाय पीना है बीमारियों को न्यौता देना

एक घंटे के भीतर चाय या कॉफी लेने से बचे

गाइडलाइन में कहा गया है कि सुबह के नाश्ते के एक घंटे के भीतर चाय या कॉफी को पीना बिमारियों का बुलावा बन सकता है। इससे शरीर में आयरन की अवशोषण की क्षमता घटती है और पोषण के बावजूद व्यक्ति एनिमिया (खून की कमी) का शिकार हो जाता है।

खाने के साथ चाय और कॉफी को कहें 'ना'

पोषण से जुड़ा मसौदा आहार मार्गदर्शक

समिति के संयोजक डॉ. डी रघुनाथ राव ने कहा कि नाश्ते या भोजन के एक घंटे तक चाय या कॉफी से दूर ही रहना चाहिए। इससे नाश्ते या भोजन में लिए गए आहार का संपूर्ण पोषण शरीर को मिल सकेगा और बीमारियों से भी बचा जा सकेगा।

दिल के मरीज कॉफी से रहे दूर

गाइडलाइन मुताबिक दिल से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को कॉफी से बचना चाहिए या बहुत कम लेना चाहिए। कॉफी पीने के बाद शरीर में रक्तचाप बढ़ता है जो हृदय की धड़कन को अनियमित बनाता है।



लोग अक्सर खाने के बाद चाय पीना पसंद करते हैं। कई लोग सुबह के नाश्ते और रात के डिनर के बाद चाय पीते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने खानपान की जो गाइडलाइन जारी की उसमें इस आदत को छोड़ने की सलाह दी गई है।

चाय पीने से हो सकती हैं ये बीमारियां

1. चाय में कैफीन की मौजूदगी शरीर में कॉर्टिसोल मतलब स्टेरॉयड हार्मोन को बढ़ाती है, जिससे शरीर को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इनमें दिल से जुड़ी प्रॉब्लम, डायबिटीज और वजन बढ़ना शामिल है।
2. चाय की पत्ती में अम्लीय गुण होते हैं जो कि भोजन के प्रोटीन के साथ मिलकर उसे सख्त बना देते हैं। इससे प्रोटीन को पचाने में मुश्किल होती है और पाचन पर असर पड़ता है।
3. चाय या कॉफी में 'टैनिन' केमिकल होता है, जो आयरन के अवशोषण को बाधित करता है। इससे मानसिक और शारीरिक थकान लगती है। जिन महिलाओं को आयरन, कैल्शियम की कमी होती है, उन्हें खाने के बाद चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए।

उदार लोग जीते हैं ज्यादा खुशहाल जीवन

उदारता लोगों को ज्यादा खुशहाल बनाती है, जो हां ये कहना है उन वैज्ञानकों का जिन्होंने अपने शोध में पाया है कि ज्यादा उदार होने से हमारे मस्तिष्क में बदलाव होता है जो हमें सुखद अनुभूति कराता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जो अपने समाज के अन्य लोगों का खयाल रखते हैं वह उन लोगों से ज्यादा खुश होते हैं जो सिर्फ अपनी जरूरतों की परवाह करते हैं और केवल अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से असीम आनंद की अनुभूति होती है।

स्विट्जरलैंड स्थित 'यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख' के शोधकर्ताओं ने पांचों को कि कैसे लोगों का मस्तिष्क इस भावना को संचारित करती है। शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया कि जो लोग दूसरों के साथ उदारता से पेश आते हैं वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा खुश होते हैं जो स्वार्थपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि हालांकि, उदारता का यह पैमाना संतुष्टि में वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। 'यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख' के फिलिप टॉबलर ने

कहा, "आपको खुशी पाने के लिए आत्म-त्याग की आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा अधिक उदार बनना पड़ेगा।" इस प्रयोग में भाग लेने वाले लोगों को दूसरों से ज्यादा उदारता से व्यवहार करने के लिए कहा गया, जिसमें पाया गया कि ये लोग अन्य से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "उदारपूर्वक व्यवहार से आप समाज में अभीष्ट व्यवहार को सुदृढ़ कर सकते हैं और खुश महसूस कर सकते हैं। यह अध्ययन 'नेचर कम्यूनिकेशंस' नामक पत्रिका में छपा है।



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में कमेटी ऑफ़ सेक्रेट्रीज की बैठक आयोजित

सूखा संभावित जिलों में पेयजल एवं चारे की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करें- मुख्य सचिव

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में कमेटी ऑफ़ सेक्रेट्रीज (सीओएस) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने मिशन कर्मयोगी, प्रक्रियाधीन भर्तियों, विभागीय स्कीमेटिक योजनाओं, बजट घोषणाओं की प्रगति, राजकाज पोर्टल पर फाइलों के निस्तारण, राजस्थान संपर्क पोर्टल तथा संभावित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रबंधन की विभागवार विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भर्तियों की समीक्षा एवं आगामी रोजगार मेले की तैयारी-

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियाँ करने के संकल्प के साथ कार्य किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 11 रोजगार मेलों एवं विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से 1 लाख 90 हजार 894 पदों पर नियुक्तियाँ दी जा चुकी हैं। इसके अलावा लगभग 1 लाख 10 हजार पदों पर भर्ती की कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है, जिनमें से 45 हजार 645 पदों पर आगामी समय में नियुक्तियाँ दी जानी संभावित हैं।

मुख्य सचिव ने आगामी रोजगार मेले में दी जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित सूचनाएं शीघ्र अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रक्रियाधीन भर्तियों में तेजी लाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्रभावी समन्वय स्थापित करने तथा न्यायालय में लंबित प्रकरणों में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही आगामी वर्ष के भर्ती परीक्षा कैलेंडर के लिए सभी विभागों को रिक्त पदों की गणना कर शीघ्र अर्थना भिजवाने के निर्देश दिए।

बजट घोषणाओं एवं स्कीमेटिक योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन-

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने शेष लंबित घोषणाओं तथा जिन घोषणाओं की स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी हैं, उनके कार्य शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।

विभागीय स्कीमेटिक योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 में सितंबर माह के अंत तक स्कीमेटिक बजट के विरुद्ध 1 लाख 1 हजार 969.52 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। यह गत वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में हुए 87 हजार 695.12 करोड़ रुपये के व्यय की



तुलना में 16.28 प्रतिशत अधिक है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत राशि के समयबद्ध उपयोग के लिए स्वयं के स्तर पर नियमित समीक्षा करने तथा केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से निरंतर समन्वय बनाकर योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए।

मिशन कर्मयोगी में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर-

मिशन कर्मयोगी के राजस्थान डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य में 8 लाख 33 हजार से अधिक कार्मिक आई-गॉट (द्वहहज्ज) प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं और प्रमुख राज्यों की केबीआई रैंकिंग में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। अब तक 82.25 लाख से अधिक नामांकन के विरुद्ध 49.12 लाख कोर्स

पूर्ण किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने नामांकन और कोर्स पूर्ण करने के अंतर को कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक शनिवार को कम से कम एक घंटा प्रशिक्षण के लिए देने के निर्देश दिए।

राजकाज पोर्टल, जनअभियोग निराकरण एवं विधानसभा प्रकरणों की समीक्षा-

मुख्य सचिव ने राजकाज पोर्टल पर विभागवार फाइल मूवमेंट की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर अब तक 54.9 लाख से अधिक ई-फाइलों का सुजन हुआ है तथा विभागों ने कम समय में फाइलों

का निस्तारण कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राजकाज वर्जन 2.0 पर वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन एपीएआर मॉड्यूल तथा एआई-आधारित स्मार्ट चैट सपोर्ट भी प्रारंभ किया गया है। मुख्य सचिव ने ई-फाइलों एवं लंबित डाक का निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

विधानसभा से संबंधित लंबित प्रश्नों एवं पीएलएस प्रकरणों की समीक्षा में बताया गया कि कुल 2 हजार 10 प्रश्नों में से 98.61 प्रतिशत (1,982) के जवाब भिजवाए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने शेष लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

राजस्थान संपर्क पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मार्च 2026 से अक्टूबर 2026 की

अवधि में दर्ज 65.92 लाख परिवारों में से 99.56 प्रतिशत (65.63 लाख) का निस्तारण किया गया है। औसत निस्तारण समय घटकर 12 दिन रह गया है तथा पत्रिकादियों की संतुष्टि का स्तर भी बढ़ा है।

सूखा संभावित जिलों में पेयजल एवं चारा प्रबंधन के निर्देश-

मुख्य सचिव ने सूखा संभावित जिलों में आमजन एवं पशुधन को राहत देने के लिए अग्रिम तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पत्रिका प्रभारी सचिवों को अपने प्रभार वाले सूखा संभावित जिलों का भ्रमण कर धरातलीय आकलन करने तथा जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल की सुचारु आपूर्ति के लिए आकस्मिक कार्या-योजना तैयार करने, आवश्यकतानुसार चारा डिपो स्थापित करने तथा गोशालाओं में पेयजल की सुमुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महिला सुरक्षा एवं बाल श्रमिकों की स्थिति में सुधार-

मुख्य सचिव ने जिलों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा बाल श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश भी दिए।

साहस, संवेदना और सूझबूझ को सलाम: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सराहे सप्ताह के पांच सफलता सूत्र, पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला

‘बेस्ट पुलिस वर्क ऑफ द वीक’ में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की उपलब्धियां चयनित; करंट से झुलसे युवक की जान बचाने से लेकर 28 महिला टप्पेबाजों की गिरफ्तारी तक

जयपुर (कासं)। हाई-टेंशन पोल पर चढ़कर युवक की जान बचाने वाला जवाब कांस्टेबल हो या धार्मिक आयोजन में जेवर चुराने वाली गैंग को दबोचने वाली टीम, राजस्थान पुलिस के जवानों ने बीते सप्ताह फिर साबित किया कि जनसेवा और अपराध के विरुद्ध सख्ती ही उनकी पहचान है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जिलों से प्राप्त सफलता कहानियों में से चयनित पांच उत्कृष्ट कार्रवाइयों को मुक्त कंठ से सराहना की है। उन्होंने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्य पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हैं और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यही समर्पण, साहस और संवेदनशीलता आगे भी बनी रहेगी और अन्य पुलिसकर्मी भी इनसे प्रेरणा लेंगे।

1. जयपुर पश्चिम: जान की परवाह किए बिना पोल पर चढ़कर बचाई युवक की जान

चेतक 60 पर ड्यूटी के दौरान पीसीआर से सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता मीके पर पहुंचा। वहां एक व्यक्ति मोतीलाल ठाकुर पुत्र गोकुल (50) निवासी गांव दराडिया थाना

रैली जिला सागर एम पी हाल बावड़ी पहाड़ी तलहटी कच्ची बस्ती 33 हजार वोल्ट के हाई-टेंशन तार की चपेट में आकर करंट से गंभीर हालत में पोल पर लटक गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना खोराबीसल के कांस्टेबल चालक सुनील कुमार (नं. 5512) ने अदम्य साहस दिखाया और तुरंत पोल पर चढ़कर घायल युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच गई। कांस्टेबल के इस साहसी कार्य को चौतरफा सराहना हो रही है।

2. जयपुर उत्तर: राजलक्ष्मी बैंक के फर्जी लोन घोटाले में 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार

थाना माणकचौक में ‘दी राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर’ में फर्जी पट्टों और दस्तावेजों के आधार पर 13 फर्जी ऋण खाते बनाकर करोड़ों रुपये हड़पने और बैंक को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज है। इसमें बैंक की पूर्व अध्यक्ष, अधिकारियों, ऋणियों और अधिवक्ताओं सहित कुल 59 आरोपी नामजद हैं। लंबे समय से फरार और बार-बार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे 10-10 हजार रुपये के

दो मुख्य इनामी आरोपियों को विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की सूचना पर गिरफ्तार किया। पुलिस अब माल और शेष आरोपियों की तलाश में जुटी है।

3. सीकर: ज्वैलर्स से डकैती के मामले में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

थाना नेछवा के गनेडी क्षेत्र में ज्वैलर्स के साथ हुई डकैती के गंभीर मामले में वांछित रामेश्वर लाल सोनी उर्फ रमेश को पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया। वह 25 हजार रुपये का इनामी और जिला स्तर की टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल था। घटना के 8 महीने बाद मिली इस सफलता से शांति अपराधी कानून के शिकंजे में आया है।

4. टोंक: निवाई में 50 लाख रुपये के अवैध पटाखे जब्त

टोंक पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में डीएसटी और निवाई थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 12 अक्टूबर 2026 को निवाई पर आदित्य प्लाजा स्थित दुकानों पर दबिश दी। बिना लाइसेंस भारी मात्रा में पटाखे रखने के आरोप में तुलसी राम चंदानी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से करीब 50 लाख रुपये मूल्य के 400 से अधिक बारूद से भरे

कार्टन जब्त किए गए। आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

5. डीडोतला-कुचामन: भागवत कथा कलश यात्रा में जेवर चुराने वाली अंतरराज्यीय गैंग की 28 महिलाएं गिरफ्तार

12 अक्टूबर 2026 को कुचामन सिटी थाना क्षेत्र में शिव मंदिर से उग्रपुरा तक निकाली गई भागवत कथा कलश यात्रा के दौरान महिलाओं के सोने-चांदी के जेवर चुराने या तोड़ने वाली शांति गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग की 28 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। वारदात को सीधे अंजाम देने वाली चार मुख्य महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। इस कार्रवाई से धार्मिक आयोजनों में सक्रिय टप्पेबाजों और चोर गिरोहों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस का हर जवान जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सदैव प्रोत्साहित किया जाएगा और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर मतदाता करें अपने मताधिकार का प्रयोग: सिंह

जयपुर (कासं)। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की उपस्थिति में सोमवार को सीकर जिले के नेछवा स्थित सनराइज स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्कूली विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने ‘एक पेड़ लोकतंत्र के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर, विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से तथा हाथों में तख्तियां लेकर आमजन को जागरूक किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मतदाता जागरूकता गीतों के माध्यम से मतदान का महत्व समझाया। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने



उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई तथा सभी से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने विभिन्न नारों और स्लोगन के माध्यम से क्षेत्रवासियों को अधिकधिक मतदान करने का संदेश दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सक्रिय भागीदारी निभाए, तभी देश का भविष्य और अधिक उज्ज्वल एवं विकसित बन सकेगा। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ यह है कि सत्थ और सुसंस्कृत समाज अपने मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण एवं गरिमापूर्ण तरीके से करे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार के अनुचित प्रलोभन में आए

प्रकार बच्चे खेल को खेल भावना से खेलते हैं, उसी प्रकार बड़ों को भी बच्चों से सीख लेते हुए परिपक्वता का परिचय देना चाहिए तथा चुनाव के दौरान आपसी संबंधों और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि मतदाता अपनी पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर भी मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप गतिविधियों के माध्यम से निरंतर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नेन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वीप प्रभारी राजपाल यादव, विकास अधिकारी रोमा सहारण सहित संबंधित अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

प्रकार बच्चे खेल को खेल भावना से खेलते हैं, उसी प्रकार बड़ों को भी बच्चों से सीख लेते हुए परिपक्वता का परिचय देना चाहिए तथा चुनाव के दौरान आपसी संबंधों और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि मतदाता अपनी पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर भी मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप गतिविधियों के माध्यम से निरंतर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नेन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वीप प्रभारी राजपाल यादव, विकास अधिकारी रोमा सहारण सहित संबंधित अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

न्यूज़ इनबॉक्स

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाईन आवेदन अब 5 नवम्बर तक

जयपुर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के द्वारा विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में नि:शुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 5 नवम्बर निर्धारित कर दी है। विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार ने बताया कि नि:शुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के हित में तारीख बढ़ाई गई है जिससे अधिकतम जरूरतमंद अभ्यर्थियों को सुविधा हो।

वीवी-जी राम जी योजना की समीक्षा बैठक

आयोजित, समय पर भुगतान एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय स्थित सभागार में वीवी-जी राम जी योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के अंतर्गत भुगतान की स्थिति एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने, दैनिक उपस्थिति एवं भुगतान की स्थिति पर नजर रखने तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने पर जोर दिया। बैठक में वीवी-जी राम जी योजना की आयुक्त श्रीमती पुष्पा सत्यानी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आमजन की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें-डॉ. आरुषि मलिक

बांसवाड़ा जिला प्रभारी सचिव ने राजस्थान संपर्क 181 पर शिकायतों की समीक्षा की

जयपुर (कासं)। बांसवाड़ा जिला प्रभारी सचिव एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषि अजेय मलिक ने सोमवार को राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का दौरा कर आमजन की शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा में बताया गया कि बांसवाड़ा जिले में दर्ज कुल 52,341 शिकायतों में से 51,574 का निस्तारण किया जा चुका है। जिले की शिकायत निस्तारण दर 98.53 प्रतिशत है तथा 767 प्रकरण लंबित हैं। निस्तारित प्रकरणों में से 35,306 में राहत प्रदान की गई है। डॉ. मलिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांसवाड़ा के शिकायतकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कार्रवाई का फीडबैक लिया। इस दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ जिले के संबंधित अन्य अधिकारी भी जुड़े। विश्वजीत सुराणा एवं मोहित ने राजस्थान, नितेश एवं कपिल ने बिजली, अर्पिता एवं गोविंद ने पेयजल तथा जितेंद्र एवं कैलाश ने नगरीय सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। डॉ. मलिक ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को संबंधित विभागों से समन्वय कर लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिलेभर में क्षेत्रीय दौरे कर आमजन की समस्याएं जानने और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए। इस दौरान डॉ. मलिक ने शिकायतों की निगरानी एवं विश्लेषण के लिए विकसित सर्वे ऑफ आइ प्रणाली का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निदेशानुसार राजस्थान संपर्क 181 पर आमजन की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण एवं प्रभावी निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने निदेशालय आईसीडीएस की योजनाओं की समीक्षा की

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभाग की शासन सचिव श्रीमती पूनम एवं निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) वासुदेव मालावत, वित्तीय सलाहकार मनोज शांडिल्य सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा शाला पूर्व देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) में किए जा रहे नवगारों की सराहना की और उन्हें निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एनईपी आधारित आधारशिला पाठ्यक्रम को और अधिक प्रभावी करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि आधारशिला के माध्यम से खेल, गतिविधियां एवं अन्वेषण आधारित शिक्षण पद्धति से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा सराहे गए प्रमुख नवाचार एवं सकारात्मक उपलब्धियां:

98.5% आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्यालयों से सह-स्थापन- प्रदेश में 98.5% आंगनबाड़ी केंद्रों (61,483 केंद्रों) को विद्यालयों के साथ सह-स्थित एवं मैप किया जा चुका है, जिससे बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में सहज प्रवेश सुनिश्चित हो रहा है।

1,000 चैंपियन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता वर्धन- विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 1,000 उच्च प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन चैंपियन के रूप में किया गया है। इसके लिए 90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये चैंपियन अपने ग्राम पंचायत की 3-4 आंगनबाड़ियों को मॉडल करेंगी।

प्रवेशोत्सव से 2.47 लाख बच्चों का नामांकन प्रोत्साहन- प्रवेशोत्सव के तहत 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 2.47 लाख से अधिक बच्चों ने निकटवर्ती विद्यालयों का भ्रमण किया, जिससे नामांकन को बढ़ावा मिला है। साथ ही अभिभावक बैठकों के माध्यम से अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है।

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर क्षेत्र-द्वितीय, गांधी नगर, जयपुर
ई-मेल - ace.regionwjaypur@yahoo.com फोन नं. 0141-2702700
कैमका- अ.मु.अ. के-2/2026-27/8315-40 दिनांक- 12/10/2026

कार्यालय आदेश
इस कार्यालय द्वारा अमोघीत निर्दिष्ट संख्या 20/2026-27 जिसके कार्य का नाम "Package 1 (work under CDI (South), Jaipur under JNN Gregate) for the work of strengthening and improvement in the Water Supply distribution network under the jurisdiction of Jaipur Nagar Nigam Greater under AMRUT 2.0 under PHED City Division-I (South) Jaipur" को अतिरिक्त कारणों से निरस्त किया जात है।
NIB No. PHE:2627A3104
UBN No. PHE:2627WLOB6557

(अजय सिंह राठौड़)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग
जयपुर क्षेत्र द्वितीय, जयपुर
DIPRC/UT943/2026